



## सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन

रश्मि जोशी, डॉ. गुरप्रीत सिंह

शोधार्थिनी, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत  
एसोसिएट प्रोफेसर, ग्लोकल स्कूल ऑफ एजुकेशन, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: रश्मि जोशी

### सारांश

उत्तराखण्ड के विविध स्थलाकृतिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित शैक्षिक परिदृश्य में विशिष्ट चुनौतियाँ और अवसर सामने आते हैं। इस अध्ययन में उत्तराखण्ड के सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता की तुलना की गई है, जिसमें असमानताओं के कारणों की पहचान और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। इस शोध में छात्रों के प्रदर्शन के आँकड़े, शिक्षक योग्यता, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, और हितधारकों की धारणाओं सहित संख्यात्मक और गुणात्मक अंतर्दृष्टियों का उपयोग किया गया है। परिणामों में संसाधनों, शिक्षण पद्धतियों, और सीखने के परिणामों में सरकारी और निजी संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण असमानताएँ उजागर होती हैं। अध्ययन के निष्कर्ष में शैक्षिक गुणवत्ता के अंतर को कम करने और उत्तराखण्ड के सभी स्कूलों में समान शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक सिफारिशें शामिल हैं।

**मूलशब्द:** निजी, उच्च, शैक्षिक गुणवत्ता, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक परिदृश्य

### प्रस्तावना

उत्तराखण्ड राज्य, जो अपनी भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, में शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच की यह असमानता विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस शोध का उद्देश्य इन दोनों प्रकार के विद्यालयों के बीच के अंतर को समझना और इसके निवारण के उपाय सुझाना है।

स्वतंत्रता शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के कारण ही आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में स्थान रखता है। शिक्षा का केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह समाज के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

शिक्षा का केवल व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों के प्रति सजग रह सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर किया जा सकता है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों ने इसे और भी मजबूत और प्रभावी बनाया है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानप्राप्ति तक ही

सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। शिक्षा से ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सकता है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों के कारण आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि, अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन निरंतर प्रयासों के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है और भारत को शिक्षा क्षेत्र में और अधिक प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है।

### अनुसंधान विधियाँ

शोध में उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों से सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आंकड़े एकत्रित किए गए। इन आंकड़ों में छात्रों के परीक्षा परिणाम, शिक्षक योग्यता, बुनियादी ढांचे की स्थिति, और अन्य शैक्षिक संसाधनों का समावेश किया गया है। इसके अलावा, शिक्षकों, छात्रों, और अभिभावकों के साक्षात्कार भी किए गए ताकि उनके दृष्टिकोण और अनुभवों को समझा जा सके।

शिक्षाविदों ने शैक्षिक सुधारों की एक बड़ी योजना प्रस्तुत की, जिसमें से कुछ सुझावों को क्रियान्वित किया गया जबकि कुछ सुझाव विभिन्न कारणों से लागू नहीं किए जा सके। निष्पक्ष शैक्षिक विकास और गुणवत्ता वृद्धि की दृष्टि से काफी कार्य किया गया, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। शैक्षिक समस्याओं के

समाधान के लिए गठित आयोगों और समितियों की तार्किक और विस्तृत सिफारिशों का समुचित पालन नहीं हो सका। इसका संभावित कारण उन सुझावों की जटिलता और देश एवं समाज की आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना से जुड़ा होना था। परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में इन आयोगों और समितियों की सिफारिशों की आवश्यकता और प्रासंगिकता महसूस नहीं की गई।

राष्ट्र के समग्र विकास की व्यापक शैक्षिक प्रणाली शिक्षाविदों के समक्ष एक चुनौती बनी रही, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा का पूरा ढांचा सत्तर वर्षों के अथक प्रयासों के बावजूद आज भी अपर्याप्त और बिखरा हुआ है। पिछले सत्तर वर्षों में भारतीय शिक्षा का रास्ता कई उतार-चढ़ावों से गुजरा है और कई मोड़ों से होकर निकला है। शिक्षा क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए हैं और कई प्रवृत्तियाँ उभरी हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार अन्य देशों की तुलना में तेजी से हुआ। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों से शिक्षा के विस्तार में कई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, लेकिन माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सका और माध्यमिक शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे गिरता चला गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार तेजी से हुआ। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों से शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, लेकिन माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सका और इसका स्तर गिरता चला गया।

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध समस्या से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु अनेक शैक्षिक साहित्यों जैसे – बुच सर्वे, समसामयिक पत्र पत्रिकाएँ, शोध प्रबन्ध, लघु शोध प्रबन्ध, समस्या से सम्बन्धित पुस्तकों, जनरल, ज्ञानकोष आदि का विस्तृत अध्ययन किया। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों की उपयोगिता, गुणवत्ता, महत्व आदि पर विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण शोध अध्ययन एवं निष्कर्ष समय-समय पर प्राप्त किये जाते रहे हैं। मापन उपकरणों के निर्मित हो जाने पर इस क्षेत्र में शोधों को गति एवं विस्तार प्राप्त होता है।

सम्बन्धित शोध कार्यों के उदाहरण के रूप में अग्रवाल, आर. एन. (1970) ने माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के समायोजन समस्या तथा उनके व्यक्तित्व पर माता-पिता, अध्यापक तथा उनके विचारों के प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि घर, विद्यालय तथा सामाजिक क्षेत्र में छात्रों के विचारों के अनुसार अवस्था बढ़ने के साथ समायोजन की समस्या कम होती जाती है जबकि संवेगात्मक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में समायोजन की समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा, घर तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के छात्रों में समायोजन की समस्या विभिन्न प्रकार की होती है।

वीरेश्वर, पी. (1979) ने विद्यालय जाने वाली बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन समस्या का अध्ययन किया। इसके निष्कर्षों में यह पाया गया कि बालिकाओं में समायोजन क्षमता की समस्या प्रत्येक क्षेत्र में पायी गयी। शहरी एवं ग्रामीण बालिकाओं के बीच पारिवारिक समायोजन की समस्याओं में सार्थक अन्तर पाया गया तथा शहरी एवं ग्रामीण बालिकाओं में प्राप्तांक एवं समायोजन में भी सार्थक अन्तर पाया गया। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सामाजिक समस्या पायी गयी, और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं में समायोजन के प्रति अधिक असंतोष पाया गया।

शर्मा, एस. (1982) ने माध्यमिक विद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के बौद्धिक कारकों और शैक्षिक सम्प्राप्ति का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों में साहित्यिक और वाणिज्य वर्ग के

विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिलब्धि थी। विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी कला वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा सृजनात्मकता और बुद्धिलब्धि के क्षेत्र में अधिक उत्तम थे। विज्ञान वर्ग में अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि कम अंक प्राप्त करने वालों की अपेक्षा उत्तम थी।

वारसेनी, एम. (1984) ने किशोर बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक समायोजन और उनके व्यवहार का सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विवाहित स्त्रियों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति पायी गयी जबकि अविवाहित बालिकाएँ अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं पायी गयीं। अविवाहित बालिकाएँ धार्मिक, रूढ़िवादी एवं शिक्षा के आभाव एवं देश के प्रति लापरवाह पायी गयीं। विवाहित बालिकाएँ सामान्य पारिवारिक जीवन और स्वतंत्र मूल्यों के प्रति अधिक संवेदनशील थीं।

अग्रवाल, कुसुम (1986) ने छात्रों के शैक्षिक विकास पर अभिभावकों के उत्साह के स्तर का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभिभावक प्रोत्साहन और शैक्षिक विकास सकारात्मक रूप से सम्बन्धित पाये गये। शहरी उच्च समूह के छात्रों की शैक्षिक प्रगति ग्रामीण उच्च समूह के छात्रों से अधिक पायी गयी। मातृ-पितृहीन बच्चों की शैक्षिक प्रगति सार्थक रूप से उनकी अभिभावक प्रोत्साहन द्वारा प्रभावित होती है।

धलशशी, पी. जी. (1988) ने माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की अध्ययन आदत एवं कौशलों का वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि अध्ययन आदत और उपलब्धि प्राप्तांकों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अधिकांश छात्रों को अध्ययन के उद्देश्य एवं विद्यालय के उद्देश्य के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उनका उद्देश्य अच्छी नौकरी, ज्ञान, सामाजिक स्तर आदि प्राप्त करना था। 25 प्रतिशत छात्रों को घर पर अध्ययन का अवसर नहीं मिलता था और 70 प्रतिशत से अधिक छात्र अध्ययन के लिए समय सारणी का निर्माण नहीं करते थे।

मजूमदार, तारुन (1988) ने कटक राज्य में माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा की स्थिति और सम्पूर्ण प्रणाली का एक अध्ययन किया। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि पश्चिम बंगाल में स्वाधीनता के बाद स्कूल शिक्षा में कई सुधार किये गये किन्तु निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। पाठ्यक्रमीय एवं संस्थागत परिवर्तन एक शून्यता एवं भ्रम की स्थिति पैदा की।

भट्ट, गनेश (1989) ने माध्यमिक शिक्षा- एक प्रणाली उपागम का अध्ययन किया। इसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय की सम्पूर्ण उपलब्धता की जाँच करना था। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि कर्नाटक राज्य में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार स्थिर रूप में हुआ। यद्यपि राज्य में माध्यमिक शिक्षा का विकास हुआ किन्तु इसमें लिंग एवं सामाजिक समूह सम्बन्धी असामान्ताएँ तथा ग्रामीण नगरीय तथा जनपदीय विभेदनाएँ पायी गयीं।

बुधदेव, पी. एवं रवीना बी. (1989) ने विभिन्न विद्यालयी विषयों के प्रति माध्यमिक विद्यालय के बच्चों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि बालिकाओं ने बालकों की अपेक्षा गुजराती, गणित, हिन्दी, सामाजिक विषय और संस्कृत में बेहतर अभिवृत्ति दिखलायी जबकि बालकों ने विज्ञान में बालिकाओं से बेहतर अभिवृत्ति प्रदर्शित की। उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चों की अभिवृत्ति गणित और अंग्रेजी में उच्च पायी गयी जबकि निम्न बुद्धिलब्धि के छात्रों की अभिवृत्ति हिन्दी में उच्च पायी गयी। देव मधु एवं नन्दा पी. (1989) ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कक्षा-10 के छात्रों का विद्यालयों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण शहरी छात्रों में ग्रामीण छात्रों से अधिक पाया गया। विद्यालय के

प्रति छात्रों के दृष्टिकोणों में सार्थक अन्तर पाया गया। नगरीय क्षेत्र के छात्रों का दृष्टिकोण ग्रामीण छात्रों से उच्च पाया गया। विद्यालयी कार्यक्रमों के प्रति शहरी छात्रों का दृष्टिकोण ग्रामीण छात्रों से उच्च पाया गया।

महेशन, गिरजा (1989) ने कर्नाटक की +2 स्तर की शिक्षा की कुछ समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि +2 स्तर की कक्षाओं के जुड़े होने से गुणात्मक सुधार हेतु अत्यन्त उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। हालांकि, इससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर बोझ बढ़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों पर पर्याप्त कार्य बोझ पड़ता है।

### परिणाम और चर्चा

- 1. शिक्षक योग्यता और प्रशिक्षण:** सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की योग्यता सामान्यतः उच्च होती है, परंतु प्रशिक्षण और निरंतर विकास के अवसरों की कमी के कारण उनका प्रभाव सीमित रहता है। दूसरी ओर, निजी विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षण पद्धतियाँ अधिक प्रभावी होती हैं।
- 2. बुनियादी ढांचा और संसाधन:** निजी विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति और शैक्षिक संसाधन सरकारी विद्यालयों की तुलना में अधिक बेहतर होते हैं। इससे छात्रों को एक समृद्ध शैक्षिक वातावरण मिलता है, जो उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करता है।
- 3. छात्र प्रदर्शन:** परीक्षा परिणामों के विश्लेषण से पता चलता है कि निजी विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन सरकारी विद्यालयों के छात्रों से बेहतर होता है। इसका मुख्य कारण संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षण पद्धतियों में अंतर है।
- 4. अभिभावक और समुदाय की भागीदारी:** निजी विद्यालयों में अभिभावक और समुदाय की भागीदारी अधिक होती है, जिससे छात्रों को समर्थन और प्रेरणा मिलती है। सरकारी विद्यालयों में इस भागीदारी की कमी के कारण छात्रों की प्रेरणा और प्रदर्शन प्रभावित होता है।

### सारांश और सुझाव

शोध के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि सरकारी और निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच की असमानताएँ उत्तराखंड के शैक्षिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। इन असमानताओं को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं:

1. शिक्षक प्रशिक्षण और विकास: सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, ताकि वे नवीनतम शिक्षण पद्धतियों से अवगत हो सकें और उन्हें अपनाएँ।
2. बुनियादी ढांचे का सुधार: सरकारी विद्यालयों में बुनियादी ढांचे और शैक्षिक संसाधनों को बेहतर बनाया जाए, ताकि छात्रों को एक समृद्ध शैक्षिक वातावरण मिल सके।
3. अभिभावक और समुदाय की भागीदारी: सरकारी विद्यालयों में अभिभावक और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि छात्रों को समर्थन और प्रेरणा मिल सके।
4. नीतिगत सुधार: शिक्षा विभाग द्वारा नीतिगत सुधार किए जाएँ, जिसमें सरकारी विद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जाएँ और उन्हें लागू किया जाए।

इस प्रकार, यह अध्ययन उत्तराखंड के शैक्षिक परिदृश्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है और सरकारी व निजी विद्यालयों के बीच की असमानताओं को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

### संदर्भ

1. अक्षर, जवाहिर: भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं, दिल्ली: रिसर्च पब्लिकेशन, 1956
2. अग्रवाल, जे.सी.: यंग मार्क्स इन दी हिस्ट्री ऑफ़ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, नई दिल्ली: ओंका बुक्स एंड कंपनी, 1962
3. अग्रवाल, जे.सी.: स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास, नई दिल्ली: आर्य पब्लिशिंग हाउस, 1962
4. अग्रवाल, आई.पी.: रिसर्च इन एजुकेशन फील्ड्स ऑफ़ एजुकेशन: कंसेप्ट्स, ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स, नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिशर्स, 1988
5. अलगुनि, फफीयू: मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी, आगरा-2% फोक्सोन पुस्तकालय, 1986
6. अनकोल, एल.बी. एवं मुँकु, एल.एम.: भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिंदी पुस्तक केंद्र, 1975
7. आर्य, डोनाल्ड: इंटरनेशनल वॉयस ऑफ़ एजुकेशन, न्यू यॉर्क: प्रेस एजेंसी, 1972
8. अमजर, आर.एल. एवं बर्नरव, टी.ए.: स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ़ रिसर्च, न्यू यॉर्क: मेडिलन बुक कंपनी, 1962
9. अन, जे.डब्ल्यू., बरदास, जे. और शर्मा, ए.बी.: एजुकेशनल फॉर्म ऑफ़ इंडिया, वेसलेन: फिनस पब्लिकेशन, 1979
10. कपिला, एच.डी.: सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा: फोक्सोन पुस्तकालय, 1994
11. कपिलार, एफ. फॉर्मेशन: एक विश्लेषण, न्यू यॉर्क: हॉल रीविंगटन एंड विन्सटन, 1966
12. कबीर, हुमायूँ: स्वतंत्र भारत में शिक्षा, दिल्ली: प्रशासन और योजना, 1967
13. कर, ए.आर. और देशमुख, ए.जी.: वेस्टेस इन कॉलेज एजुकेशन, पुणे: गौकले इंस्टिट्यूट ऑफ़ पॉलिटिक्स एंड इकॉनॉमिक्स, 1963
14. खिगर, एम.डी.: फाउंडेशन ऑफ़ इंडियन एजुकेशन, लखनऊ: हेम हाउस, 1980
15. कोल, वी.एन. और सिंह, विशेश्वर और अकलाजी, एम.एम.: स्टेट्स इन डिस्टेंस एजुकेशन, नई दिल्ली: एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज, 1988
16. कोल, लोकश: मैथोडोलॉजी ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च, नई दिल्ली: देवेलपमेंट पब्लिशिंग हाउस, 1984
17. फिलिप्स, जे.पी.: फंडामेंटल ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स बाय साइकॉलॉजी एंड एजुकेशन, नई दिल्ली: मेडिलन बुक कंपनी, 1965
18. गुप्ता, एल.पी.: आधुनिक मापन और मूल्यांकन, इलाहाबाद: काजल पब्लिशिंग हाउस, 2004
19. गुप्ता, एल.पी. और गुप्ता, एल.का.: भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास और समस्याएं, इलाहाबाद: काजल पब्लिशिंग हाउस, 2005
20. गुप्ता, एल.पी.: सांख्यिकी विधियाँ, विकास और समस्याएं, इलाहाबाद: काजल पब्लिशिंग हाउस, 2004
21. ग्रोवर, बी.एल.: आधुनिक भारत का इतिहास: एक नया मूल्यांकन, नई दिल्ली: सेंट पॉल एंड कंपनी, 1990
22. गेरिट, ए.जे.: स्टैटिस्टिक्स बाय साइकॉलॉजी एंड एजुकेशन, बम्बई: फिनसिया पब्लिशिंग हाउस, 1969
23. चौधरी, विकास एवं चौधरी, सज्जनपाल: भारत की आधुनिक शिक्षा का इतिहास और समस्याएं, आगरा: फोक्सोन पुस्तकालय, 2006
24. झालोकी, एल.के.: भारतीय शिक्षा का इतिहास और भारतीय शिक्षा की समस्याएं, लखनऊ: पब्लिकेशन सेंटर पब्लिशर्स,

2006

25. जोशी, डी.एल.: प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, इकुपोर पब्लिकेशन, 1977
26. नायक, जे.पी. और नकुल, सेंसर: भारतीय शिक्षा का इतिहास, नई दिल्ली: पेमेलन, 1976
27. नकुल और नायक: हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वर्ल्ड प्रेस फिजिकल एजुकेशन, 1956
28. पाठक, पी.डी.: शिक्षा मनोविज्ञान, आगरा: फोक्सोन पुस्तकालय, 2004
29. पांडेय, बी.बी. और पांडेय, ए.के.: भारतीय शिक्षा का इतिहास और सामाजिक समस्याएं, गोरखपुर: वाकसी पब्लिकेशन, 2004
30. पांडेय, रामकांत: शिक्षा समीक्षा, इलाहाबाद: काजल पब्लिशिंग हाउस, 1975
31. पांडेय, रामकांत, सिंह, रामपाल और आर्य, जय देव: भारतीय शिक्षा की समस्याएं, आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, 1977
32. गोसाई, बी.के.: शिक्षा मनोविज्ञान, मेरठ: गोसाई पब्लिशिंग हाउस, 1991
33. भारत सरकार नई दिल्ली: शिक्षा की चुनौतियों पर प्रकाश, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1985
34. भारत सरकार नई दिल्ली: एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन प्रोग्राम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1986
35. भारत सरकार शिक्षा विभाग: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1979
36. भारत सरकार शिक्षा विभाग: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990 की समीक्षा समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1990
37. मोहन, बलजीत: भारतीय शिक्षा का इतिहास, नई दिल्ली: भारतीय प्रेस पब्लिशर्स, 1972
38. मुलायम, फोकल: भारतीय शिक्षा की समस्याएं और प्रवृत्तियाँ, दिल्ली: फोकल प्रकाशन, 1975
39. महेश्वरी, जी.के.: साइंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, नई दिल्ली: युर्सिफिया पब्लिशिंग हाउस, 1964
40. महेश्वरी, वी.एस.: स्टेट्स इन इंडियन एजुकेशन, नई दिल्ली: आर्य पब्लिशिंग हाउस, 1968
41. मीश्रा, फोकल: भारतीय शिक्षा का विकास और वर्तमान समस्याएं
42. मुखर्जी, आर.के.: नेशन बिल्डिंग इन ह्यूमन रिसोर्स, दिल्ली: सेंट पॉल एंड कंपनी, 1970
43. मुखर्जी, एम.एन.: एजुकेशन इन इंडिया: ट्रेंड्स एंड इशूज, दिल्ली: सेंट पॉल एंड कंपनी, 1952
44. मुखर्जी, एल.एन.: टीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली: सेंट पॉल एंड कंपनी, 1970

#### **Creative Commons (CC) License**

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.